अनुपस्थित हो गए। जब उनको अनुशासनात्मक कार्यवाही का ज्ञान कराया गया तो वे भी उस दबाव डालने के अभियान में सम्मिलित हो गए। यदि एक विशिष्ट राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शहर से आकर अन्यत्र जाने के लिए राजी कर्मचारियों के विधिवत तथा शांतिपूर्ण रूप से हटाए जाने के काम में हस्तक्षेप न करते तो यह योजना सफल रहती। बस्ती से बाहर के लोग हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की बस्ती में लगातार आते रहे और उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन का वातावरण बनाया और उन्होंने कारपोरेशन के एक अधिकारी को सम्बंधित व्यक्तियों को स्थिति के स्पष्टीकरण से रोका।

प्रबंधकों की योजना के अंतर्गत मुसलमानों की आबादी के एक ही स्थान में जमाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा था तो राजनीति से प्रेरित व्यक्तियों ने यह अफवाह फैला दी कि समूचे सैक्टर २ को अधिकारियों द्वारा बलात् खाली करवाया जा रहा है और नया निर्माण किया जा रहा है तथा सभी मुस्लिम कर्मचारियों को एक ही स्थान में फिर बसाया जा रहा है और उन्हें विशाल रांची शहर में अन्य मुसलमानों से सम्पर्क स्थापित करने की सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों की योजना केवल इतनी थी कि मुस्लिम कर्मचारियों को बस्ती के कई हिस्सों में बसाया जाय जिससे कि उनमें मेलजोल की भावना तथा सुरक्षा की भावना का निर्माण हो।

हाल ही में कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने विभिन्न सैक्टरों में अतिरिक्त मकान निर्माण करने का निश्चय किया है ताकि इन कर्मचारियों का पुनर्वास किया जाये। इस काम के लिए चालू वर्ष में 20 लाख रुपये व्यय करने का विचार है।

जान-बूझकर ऐसे संशय का निर्माण किया गया कि प्रबन्धक विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में हिन्दू कर्मचारियों पर अपने वर्तमान स्थान से निकलने के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि इस प्रकार खाली किए जाने वाले मकानों का आवन्टन मुस्लिम कर्मचारियों को किया जाए। प्रबन्धकों ने इस विषय में सार्वजनिक घोषणा की है। वास्तव में प्रयास तो यह किया गया है कि मुस्लिम कर्मचारियों के एक ही स्थान पर अर्थात् आर्टीजन होस्टल में वर्तमान जमाव को तोड़ा जाय और उन्हें बस्ती के विभिन्न हिस्सों में बाँटा जाय ताकि एक तरफ तो उनके एक ही स्थान पर जमाव को रोका जा सके और दूसरी ओर उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके। इस प्रयत्नों में अनुरोध से काम लिया गया और स्वेच्छा से ही अन्यत्र चले जाने के निवेदन के आधार पर ही सारी कार्यवाही की गई है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड

1022. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री ओम प्रकाश शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के अंशधारियों ने प्रबन्धकों द्वारा करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोग किये जाने के विरुद्ध सरकार से शिकायत की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंशधारी उनकी शिकायत के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा करने वाले हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कम्पनी के कार्य की जाँच के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ग) तथा (घ). यह विषय परीक्षान्तर्गत हैं।

अफ्रीकी तथा दक्षिण अमरीकी देशों को निर्यात

1023. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के अल्प विकसित देशों को 1968 में भारत द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ख) इन देशों को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ; और

(ग) वर्ष 1969 में इन देशों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-125/69]

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. व्यापार-व्यवस्थाओं का तय किया जाना,
2. व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना,
3. अध्ययन तथा बिक्री दलों को भेजना,
4. विदेशों में विपणन सर्वेक्षण करना,
5. विदेशों में भारतीय उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करना सुकर बनाना,
6. व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का भेजना तथा बुलवाना तथा बातचीत,
7. विदेशों में भारत सरकार के वाणिज्यिक मिशनों की स्थापना।

(ग) यद्यपि वर्ष 1969 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं फिर भी इन देशों को हमारे निर्यात अधिकतम सम्भव सीमा तक बढ़ाने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस्पात कारखानों का प्रशासनिक नियंत्रण

1024. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के तीनों कारखानों का प्रबन्ध उद्योगों के विशेषज्ञों के हाथ में नहीं है परन्तु नौकरशाहों के हाथों में है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इन कारखानों के भारी घाटे पर चलाने को देखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह की भारतीय औद्योगिक तथा व्यापार प्रबन्ध सेवा स्थापित करने तथा इन कारखानों का प्रबन्ध इस सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सौंपने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो घाटे पर चल रहे इन कारखानों पर सरकारी धन व्यय करने के क्या कारण हैं ?